

Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3164

TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE JANUARY 05, 2018
PAUSHA 15, 1939 (SAKA)

NATIONAL ANOMALY COMMITTEE

QUESTION

3164. SHRI CH. MALLA REDDY:

Will the **Minister of FINANCE** be pleased to state:

- (a) whether the National Anomaly Committee (NAC) under the 7th Central Pay Commission has submitted its interim report, if so, the details thereof;
- (b) whether the Government is planning to abolish the system of formation of Pay Commission in future, if so, the details thereof and the reasons therefor;
- (c) whether the Government is considering to adjust the salaries of its employees and pensioners Dearness Allowance (DA) that crosses the 50 per cent mark, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
- (d) whether the Department of Expenditure planning to take the responsibility to regularly monitor salaries and allowances of central government employees and recommend the changes if needed, if so, the details thereof and the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI P. RADHAKRISHNAN)

- (a): The National Anomaly Committee set up by the Department of Personnel & Training in August, 2016 following the decision of the Government on the recommendations of the 7th Central Pay Commission has not yet met.
- (b) to (d): No such proposals are at present under consideration.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3164

शुक्रवार, 05 जनवरी, 2016/16 पौष, 1939 (शक)

राष्ट्रीय विसंगति संबंधी समिति

3164. श्री चामाकुरा मन्सा रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अधीन राष्ट्रीय विसंगति संबंधी समिति (एनएसी) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार भविष्य में वेतन आयोग के गठन की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए), जो 50 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं, का समायोजन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या व्यय विभाग केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की निबमित रूप से निगरानी करने की जिम्मेदारी उठाने और यदि आवश्यक हो, तो इसमें परिवर्तन की सिफारिश करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन)

- (क): सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के पश्चात् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अगस्त, 2016 में गठित राष्ट्रीय विसंगति समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।
- (ख) से (घ): इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
